P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-10* June- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सागर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अध्ययन : वर्ष 2015 से 2019 तक

Study of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Sagar District: From 2015 to 2019

Paper Submission: 05/06/2021, Date of Acceptance: 15/06/2021, Date of Publication: 22/06/2021

उतसव आनन्द
सह प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर
विश्वविद्यालय,
सागर, म.प्र., भारत

रंजना चंदेरिया
शोधार्थी,
अर्थशास्त्र विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर
विश्वविद्यालय,
सागर, म.प्र., भारत

सारांश

किसी भी देश के आर्थिक विकास की पहली सीढ़ी देश के यातायात मार्गो का विकास हैं। परिवहन व्यवस्था का विकास करके ही देश की अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता हैं। वर्तमान में जब हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में देश की परिवहन व्यवस्था को नजरअंदाज करना संभव नहीं हैं। सड़कें विकास का आधार होती हैं, जो गाँवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में परिवहन विकास के उद्देश्य को पूरा कर रही भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सागर जिले में अध्ययन किया गया हैं।

The first step in the economic development of any country is the development of the country's transport routes. The economy of the country can be developed only by developing the transport system. At present, when we are moving fast towards the goal of self-reliant India, it is not possible to ignore the country's transport system. Roads are the basis of development, which connect villages with cities. In the present research paper, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana of the Government of India, which is fulfilling the purpose of transport development, has been studied in Sagar district.

मुख्य शब्द : प्रधानमंत्री ग्राम संडक योजना, पीएम जी एस वाय, संम्पर्क विहीन बसाहट, बारहमासी, आईएपी कोर नेटवर्क, संपकर्ता।

प्रस्तावना

भारत एक विकासशील देश हैं, जहाँ विकास के लिए भारत सरकार सदैव प्रयासरत हैं। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 70 प्रतिशत जनसंख्या एवं श्रम ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत हैं। राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान हैं। ग्रामीण भारत के कायाकल्प में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। भारत के पास वर्तमान में विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क तंत्र हैं, इनमें सबसे अहम भूमिका ग्रामीण सड़कों की हैं, जो देश के कुल सड़क नेटवर्क का करीब 80 फीसदी हैं। ग्रामीण सड़के आज देश की जीवन रेखा हैं। भारत सरकार के नए भारत दृष्टिकोण का केन्द्र ग्रामीण भारत और कृषि अर्थव्यवस्था हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़के, संचार सुविधाओं, पेयजल और सिंचाई, आवास, शौचालय, बिजली और रसोई गैस जैसी सुविधाओं की पहुँच व्यापक होने और बड़े स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता के कारण ग्रामीणों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला हैं।

वर्तमान में जब हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में ग्रामीण विकास को नजरअंदाज करना संभव नहीं हैं। ग्रामीण विकास के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। सड़के ग्रामीण विकास का आधार होती हैं। सड़क ही वह आधार हैं, जो गाँवों को शहरो से जोड़ती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. सागर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अध्ययन करना।
2. सागर जिले में वर्ष 2015 से 2019 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किए गए कार्यो का विश्लेषण करना।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध पत्र जिसका शीर्षक ''सागर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अध्ययनः वर्ष 2015 से 2019 तक'' हैं। मेरे द्वारा अध्ययन का क्षेत्र मध्यप्रदेश के सागर जिले को चुना गया हैं। सागर जिला मध्यप्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित हैं। जहाँ जनगणना 2011 के अनुसार कुल 23,78,548 जनसंख्या निवासरत हैं। जिले में नगरीय जनसंख्या जिले की कुल जनसंख्या की 29.8 प्रतिशत हैं, एवं ग्रामीण जनसंख्या जिले की कुल जनसंख्या की 70.2 प्रतिशत हैं। जिले का कुल क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर हैं।

साहित्यावलोकन

कुमार, अरविंद, (2021), '' सतत् ग्रामीण विकास में अवसंरचना क्षेत्रों का महत्व '', प्रस्तुत शोध पत्र में बताया गया हैं, कि देश के ग्रामीण विकास में अवसंरचना क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं। शोध में बताया गया हैं, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण जीवन में व्यापक बदलाव आया हैं। पिछले पाँच वर्षो में डिजिटल भारत ने शहरी और ग्रामीण भारत के बीच के डिजिटल अंतर को दूर कर दिया हैं।

जाखड़, कुमार, अरविंद, (2020), '' प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभावः चूरू ब्लाक–जिला चूरू, राजस्थान का एक भौगोलिक अध्ययन '', प्रस्तुत शोध पत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े लोगों और सम्बद्ध अधिवासों का सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन किया गया हैं। शोध में शिक्षा, स्वास्थ, प्रशासनिक केन्द्रों से जुड़ाव, आर्थिक विकास में योजना के प्रभाव का अध्ययन किया गया हैं।

इतवार, मधुकर, (2019), '' प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन और सागर जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सागर जिला '', प्रस्तुत शोध कार्य में सागर जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया हैं। शोध कार्य में बताया गया हैं, कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान हैं। शोध में योजना की समस्याओं एवं उनके समाधान का अध्ययन किया गया हैं।

एम, वागले, एपी, सिंह, एके, सरकार, (2019), '' स्थानीय आजीविका विविधीकरण पर ग्रामीण सड़क निर्माण का प्रभावः झुंझुनू जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साक्ष्य, भारत '', प्रस्तुत शोध पत्र अस्पष्ट ढांचे को नियोजित करके आवास स्तर पर लक्षित आबादी की आजीविका विविधीकरण पर ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के प्रभाव की जाँच करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता हैं। यह घरेलू आय पर विविधीकरण और नियंत्रण चर के प्रभाव का करने के लिए अर्थमितीय मॉडलिंग भी करता हैं।

ए, रहमान, (2019), '' प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण असम के परिवर्तन में इसकी भूमिकाः असम के कामरूप जिले में एक केस स्टडी '', प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पीएमजीएसवाय के तहत बेहतर ग्रामीण संर्पक के प्रभाव की जांच करने का प्रयास किया गया हैं। इसके लिए असम के कामरूप जिले में दो केस स्टडी की गई हैं।

ए, एम. काले, एस.एस. पिमपलीकर, (2017), '' प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः पास्ट, पिर्जेन्ट एण्ड फ्यूचर '', प्रस्तुत शोध पत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भूत, भविष्य और वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया गया हैं। शेध में बताया गया हैं, कि योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों का निर्माण हो रहा हैं, जिससे सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संपर्कता स्थापित हो रही हैं।

सिंह, योगेन्द्र, (2015), ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययनः जिला बस्तर'', प्रस्तुत शोध पत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बस्तर जिले के विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया हैं। शोध पत्र में बताया गया हैं, कि सड़क ग्रामीण क्षेत्रो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकास की पहली सीढ़ी सड़क निर्माण हैं।

यू, कोंच, (2014), '' ग्रामीण परिवहनः असम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) का एक अध्ययन '', प्रस्तुत शोध पत्र असम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रदर्शन की जांच करने का प्रयास करता हैं। अध्ययन से पता चलता हैं, कि असम में पीएमजीएसवाय का कार्यान्वयन इसकी सफलता की ओर एक बेहतर संकेत हैं।

ओ. पी., मिनोचा, (2006), '' विकास के लिए क्षमता निर्माणः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आकलन '', प्रस्तुत शोध पत्र में बताया गया हैं, कि कैसे सुदृढ़ शासन की संस्था के रूप में लोक सेवा की विश्वसनीयता को बहाल किया जाय। यह पत्र विकास के लिए क्षमता निर्माण के वैचारिक ढांचे की जांच करने और व्यक्तिगत क्षमता कार्यक्रमों में से एक में संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमता निर्माण की आवश्यकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता हैं।

सागर एक परिचय

सागर जिला मध्यप्रदेश के उत्तर मध्य क्षेत्र में स्थित हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार सागर जिला $23^0 10'$ से $24^0 27'$ उत्तरी अंक्षाश और $78^0 4'$ से $79^0 21'$ पूर्वी देशांतर तक फैला हैं। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई 55 मीटर हैं। जिले की सीमाएँ मध्यप्रदेश के छः जिलों छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा, नरसिंहपुर, रायसेन, दमोह व अशोकनगर एवं उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले को छूती हैं। जिले दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती हैं। जिले में 11 विकासखण्ड बीना, खुरई, मालथौन, बण्डा, शाहगढ़, राहतगढ़, सागर, रहली, जैसीनगर, देवरी तथा केसली हैं। जिले का क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 23,78,458 हैं। जिसमें पुरूषों एवं महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 12,56,257 एवं 11,22,201 हैं। नगरीय एवं ग्रामीण

जनसंख्या क्रमशः 7,08,796 एवं 16,69,662 हैं। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 29.8 प्रतिशत एवं 70.2 प्रतिशत हैं। जिले की साक्षरता दर 76.5 प्रतिशत हैं। सागर जिले में 11 विकासखण्डो में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 755 हैं, एवं जिले में कुल गाँवों की संख्या 2244 हैं।

सागर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ वर्ष 2000 से हुआ हैं। जिले में योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क कार्यों की कुल संख्या 393 हैं, जिनकी कुल लंबाई 1350.325 किलोमीटर हैं, जिसे रूपये 41114.83 लाख में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित हैं। जिससे जिले की 545 संपर्क विहीन बसाहटों को संपर्कता प्राप्त होनी हैं। सागर जिले में 24 एलसीबी कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति हैं, जो रूपये 4392.96 लाख की लागत में 1247. 920 मीटर लंबाई के हैं। जिन्हें में 381 सड़क कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जिससे 533 संपर्कविहीन बसाहटों को बारहमासी संपर्कता प्राप्त हुई हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक परिचय

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं। सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 तथा इससे अधिक आबादी वाले संपर्कविहीन पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़को से जोड़ने के लिए दिनांक 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन संपर्कता के अतिरिक्त अन्य जिला मार्गो एवं ग्रामीण मार्गो का निर्माण एवं उन्नयन भी किया जा रहा हैं। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में आईएपी जिलों में संपर्कविहीन ग्रामों (आबादी 250 तक) को पक्की सड़क सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं। ग्रामीण सड़क अधोसंरचना के उच्च विकास हेतु आधुनिकतम/नवीन तकनीकी के साथ–साथ उच्च गुणवत्ता हासिल की जा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकारों की मदद ली जा कर उन्नत मापदण्डों के आधार पर एक समयबद्ध कार्यप्रणाली में अनुभवी ठेकेदारों द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर गठित प्राधिकरण द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के संधारण का कार्य राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से सतत् कराया जाता हैं। साथ ही भारी यातायात से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के क्रस्ट उन्नयन का कार्य भी आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

1. कोरनेटवर्क पर आधारित प्लानिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े मापदण्ड निर्माण पश्चात् 5–10 वर्षो की अवधि पूर्ण कर चुकी सड़कों का रखरखाव भी योजना में शामिल होगा, कार्यो की गुणवत्ता निगरानी/नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मानिटर्स की व्यवस्था, योजना से संबंधित कार्यो में संपूर्ण पारदर्शिता, ऑनलाइन मानिटरिंग, ई–टेंडरिंग, ई–पेमेंन्ट व ई– मार्ग आदि इस कार्यक्रम की विशेषताएँ हैं।
2. पीएमजीएसवाय–।।। योजना के अन्तर्गत उन्नयन के लिए मार्गो को चिन्हित किए जाने की प्रक्रिया पूर्णतः सूचना प्रोद्योगिकी (आई. टी.) आधारित हैं। विद्यमान समस्त मार्गो एवं ग्रामों का जी. आई. एस. आधारित डाटा तैयार कर शिक्षण, चिकित्सा, ग्रामीण कृषि बाजार एवं यातायात की सुविधाओं के फोटोग्राफ्स जियो टैग कर सुविधाओं में पहुँचने हेतु मार्गो की उपयोगिता के अनुसार सिस्टम जनरेटेड ट्रेसमैप से मार्गो की रैंक प्राप्त कर उपयोगिता मूल्य के अनुसार सिस्टम जनरेटेड प्राथमिकता सूची से वरीयता के क्रम पर मार्गो के उन्नयन का प्रस्ताव वरीयता के अनुसार किया जाना हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीन भागों में विभाजित हैं। योजना तीन चरणों में कार्य पूर्ण करने के लिए प्रस्तावित हैं। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीन चरण/भाग निम्नवत् हैंः–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग– I

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग–। के अन्तर्गत अद्यतन स्थिति में रू. 22,169 करोड़ राशि का व्यय करते हुए 18,780 मार्गो जिनकी लंबाई 72,771 किलोमीटर हैं का निर्माण किया गया हैं, 17,436 संपर्कविहीन बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई।
4. वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 583 किलोमीटर लंबाई के 512 मार्गो एवं 118 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण करते हुए रूपये 587 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिससे 180 बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हुई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग– II

5. भारत सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व से विद्यमान अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य से पीएमजीएसवाय–।। योजना प्रारंभ की गई हैं, जिसके तहत् प्रदेश को 4,984 किलोमीटर मार्गो के उन्नयन की तथा 245 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। अब तक 4,713 किलोमीटर लंबाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। साथ ही 148 वृहद पुलों का भी निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
6. वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 1,296 किलोमीटर लंबाई के 191 मार्गो एवं 92 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण करते हुए रूपये 1,211 करोड़ की राशि व्यय की गई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना– III

15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–।।। प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य पूर्व से निर्धारित ग्रामीण मार्गो, जो कि शिक्षण, चिकित्सा, कृषि बाजार एवं यातायात अवसंरचना को जोड़ते हैं, का उन्नयन कार्य किया जाना हैं। भारत सरकार से प्रदेश को 12,362 किलोमीटर मार्गो का आवंटन प्राप्त हुआ हैं, एवं योजना की अवधि वर्ष 2025 तक निर्धारित की गई। वित्तीय वर्ष 2019–2020 बैच–1 में 108 मार्गो, 1444

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-10* June- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

किलोमीटर लंबाई एवं 27 नग बड़े पुलों हेतु रू. 1176.11 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त कर एजेंसी निर्धारण की कार्यवाही कर ली गई हैं तथा कार्य प्रारंभ हैं।

सागर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (वर्ष 2015–2016)

कार्य किस्म	संपर्कता किस्म	प्रस्ताव स्वीकृति				पूर्ण किए गए कार्य			व्यय	
		कार्यो की संख्या	कुल लंबाई	शामिल की गई कुल बसाहटों की संख्या	लागत	कार्यो की संख्या	कुल लंबाई	शामिल की गई बसाहटों की संख्या	एमपीआर	खाता
सड़कें	नई संपर्कता	13	10.830	14	672.58	12	10.130	13	—	170705.01
	उन्नयन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	13	10.830	14	673	12	10.130	13	—	170705.01
वृहद पुल	नई संपर्कता	—	—	—	—	—	—	—	—	8401.25
	उन्नयन	2	120.000	—	343.71	2	120.000	—	—	9982.88
	योग	2	120.000	—	344	2	120.000	—	—	18384.13

स्रोतः– मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण परियोजना क्रियान्वयन कार्यालय सागर (म.प्र.) से प्राप्त।
(समस्त सड़कों की लंबाई किलोमीटर में, वृहद पुलों की लंबाई मीटर में एवं लागत लाखों में)

सागर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2016–2017

कार्य किस्म	संपर्कता किस्म	प्रस्ताव स्वीकृति				पूर्ण किए गए कार्य			व्यय	
		कार्यो की संख्या	कुल लंबीई	शामिल की गई कुल बसाहटों की संख्या	लागत	कार्यो की संख्या	कुल लंबाई	शामिल की गई बसाहटों की संख्या	एमपीआर	खाता
सड़कें	नई संपर्कता	100	270.205	109	13918.46	91	243.855	100	11.09	71843.49
	उन्नयन	5	14.430	6	592.26	5	14.430	6	—	31974.03
	योग	105	284.635	115	14511	96	258.285	106	11.09	103817.52
वृहद पुल	नई संपर्कता	—	—	—	—	—	—	—	—	20166.69
	उन्नयन	1	114.400	—	269.03	1	114.400	—	—	18375.30
	योग	1	114.400	—	269	1	114.400	—	—	38541.99

स्रोतः– मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण परियोजना क्रियान्वयन कार्यालय सागर (म.प्र.) से प्राप्त।
(समस्त सड़कों की लंबाई किलोमीटर में, वृहद पुलों की लंबाई मीटर में एवं लागत लाखों में)

सागर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2017–2018

कार्य किस्म	संपर्कता किस्म	प्रस्ताव स्वीकृति				पूर्ण किए गए कार्य			व्यय	
		कार्यो की संख्या	कुल लंबाई	शामिल की गई बसाहटों की संख्या	लागत	कार्यो की संख्या	कुल लंबाई	शामिल की गई बसाहटों की संख्या	एमपीआर	खाता
सड़कें	नई संपर्कता	1	0.600	1	60.36	1	0.600	1	—	20251.71
	उन्नयन	5	8.200	5	520.09	3	4.800	3	—	27031.58
	योग	6	8.800	6	580	4	5.400	4	—	47283.29
वृहद पुल	नई संपर्कता	—	—	—	—	—	—	—	—	5271.43
	उन्नयन	—	—	—	—	—	—	—	—	1660.07
	योग	—	—	—	—	—	—	—	—	6931.50

स्रोतः– मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण परियोजना क्रियान्वयन कार्यालय सागर (म.प्र.) से प्राप्त।
(समस्त सड़कों की लंबाई किलोमीटर में, वृहद पुलों की लंबाई मीटर में एवं लागत लाखों में)

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-10* June- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सागर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2018–2019

कार्य किस्म	संपर्कता किस्म	प्रस्ताव स्वीकृति				पूर्ण किए गए कार्य			व्यय	
		कार्यो की संख्या	कुल लंबाई	शामिल की गई बसाहटों की संख्या	लागत	कार्यो की संख्या	कुल लंबाई	शामिल की गई बसाहटों की संख्या	एमपीआर	खाता
सड़कें	नई संपर्कता	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उन्नयन	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–
वृहद पुल	नई संपर्कता	6	332.800	–	1540.96	–	–	–	–	10472.99
	उन्नयन	–	–	–	–	–	–	–	–	5351.38
	योग	6	332.800	–	1541	–	–	–	–	15824.37

स्रोतः– मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्रधिकरण परियोजना क्रियान्वयन कार्यालय सागर (म.प्र.) से प्राप्त।

(समस्त सड़कों की लंबाई किलोमीटर में, वृहद पुलों की लंबाई मीटर में एवं लागत लाखों में)

सागर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विश्लेषण (वर्ष 2015 से 2019 तक):–

1. सागर जिले में वर्ष 2015–2016 की अवधि में कुल 13 सड़क निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जो रूपये 672.58 लाख की लागत में 10.830 किलोमीटर की लंबाई का निर्माण हैं, जिससे 14 संपर्कविहीन बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हैं।
   प्रस्ताव स्वीकृत कार्यो में से 12 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किए गए, जिनकी लंबाई 10.130 किलोमीटर हैं, जिससे 13 बसाहटों को बारहमासी संपर्कता प्राप्त हुई हैं।
2. जिले में वर्ष 2015–2016 में 2 एलसीबी निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जो रूपये 343.71 लाख की लागत में 120 मीटर की लंबाई का निर्माण कार्य हैं। योजना अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृत संपूर्ण कार्य पूर्ण रूप से हुआ।
3. सागर जिले में वर्ष 2016–2017 में कुल 105 सड़क निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जो रूपये 14511 लाख की लागत में 284.635 किलोमीटर की लंबाई का निर्माण कार्य हैं, जिससे 115 संपर्कविहीन बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हैं।
   प्रस्ताव स्वीकृत कार्यो में से कुल 96 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किए गए। जिनकी लंबाई 258.285 किलोमीटर हैं, जिससे 106 बसाहटो को संपर्कता प्राप्त हुई हैं।
4. जिले में वर्ष 2016–2017 में 1 एलसीबी निर्माण कार्य का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जो रूपये 269 लाख की लागत में 114.400 मीटर की लंबाई का निर्माण कार्य हैं। योजना अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृत संपूर्ण कार्य पूर्ण रूप से हुआ।
5. सागर जिले में वर्ष 2017–2018 में कुल 6 सड़क निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जो रूपये 580 लाख की लागत में 8.800 किलोमीटर की लंबाई का निर्माण कार्य हैं, जिससे 6 संपर्कविहीन बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हैं।
   प्रस्ताव स्वीकृत कार्यो में से कुल 4 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हुए, जिनकी लंबाई 5.400 किलोमीटर हैं। जिससे 4 बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हुई।
6. सागर जिले में वर्ष 2018–2019 में कुल 6 एलसीबी निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जो रूपये 1541 लाख की लागत में 338.200 मीटर की लंबाई का निर्माण कार्य हैं। योजना अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृत कार्य अपूर्ण हैं।
7. सागर जिले में वर्ष 2015–2019 की अवधि में कुल 124 सड़क निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जिसमें 112 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हुए हैं।
8. सागर जिले में वर्ष 2015–2019 की अवधि में कुल 9 एलसीबी निर्माण कार्यो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जिसमें से कुल 3 एलसीबी निर्माण कार्य पूर्ण हुए हैं।
9. जिले में वर्ष 2015–2019 की अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 124 संपर्कविहीन बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हुई हैं।
10. जिले में वर्ष 2015–2019 की अवधि में योजना के कार्य निर्माण में कुल व्यय रूपये 411971.89 लाख हुआ हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिला हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि के काम में आने वाले वाहनों के अलावा निजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी हैं। पहले 60 किलोमीटर देहाती सड़क रोज बनती थी, जो अब 133 किलोमीटर से अधिक हो गई हैं। सड़कों के निर्माण से अपारम्परिक सामग्रियों जैसे– बेकार प्लास्टिक, फ्लाई एश समेत कई धातुओं के बेकार हिस्सों का उपयोग भी किया जा रहा हैं। हरित प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। भारत सरकार की ओर से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए मास्टर ट्रेनरों, इंजीनियर्स और ठेकेदारों को प्रशिक्षण देकर व्यापक क्षमता विकास भी किया गया हैं।

भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी हैं। देश के गाँवों में चहुमुखी विकास की एक नई लहर चल रही हैं, जिसका ग्रामीण समुदाय के पारिवारिक–सामाजिक जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा हैं। सड़क सुविधा प्राप्त होने से ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार हुआ हैं। ग्रामीणों की शहरों से संपर्कता स्थापित हुई हैं, जिससे ग्रामीणों को जीवन–स्तर में सुधार के नए–नए अवसर प्राप्त हुए हैं। ग्रामीणों को स्थायी एवं अस्थायी रोजगार प्राप्त हुए हैं, ग्रामीण सड़को के निर्माण से ग्रामीण शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आवागमन, कृषि, बाजार एवं अन्य कई विकास मापदण्डों में सुधार हुआ हैं।

भारत–सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अपने विकास लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिश में प्रयासरत् हैं। एवं योजना से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उठाया गया कदम सफल एवं सराहनीय हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *कुमार, अरविंद, ''सतत् ग्रामीण विकास में अवसंरचना क्षेत्र का महत्व'', ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरूक्षेत्र, 2021।*
2. *जाखड़, कुमार, अरविंद, ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, मॉर्डन मेनेजमेन्ट एप्लाईड साइन्स एण्ड सोशल साइन्स, 2020।*
3. *एम, वागले, एपी, सिंह, एके, सरकार, ''स्थानीय आजिविका विविधीकरण पर ग्रामीण सड़क निर्माण का प्रभाव'', जियोजर्नल, 2019, स्प्रिंगर।*
4. *ए, रहमान, ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण असम के परिवर्तन में इसकी भूमिका'', एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडायमेंशनल रिसर्च (एजेएमआर) 8(7),77–94, 2019।*
5. *ए, एम, काले, एस, एस, पिंमपलीकर, ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः पास्ट, पिर्जेन्ट एण्ड फ्यूचर'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस साइन्टिफिक रिसर्च एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेन्ड्स, 2017।*
6. *सिंह, योगेन्द्र, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः एनालीटिकल स्टडी ऑफ द डेवलपमेन्ट ऑफ द बस्तर डिस्ट्रिक'', सीएलईएआर इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एण्ड मेनेजमेन्ट, 2015।*
7. *यू, कोंच, ''ग्रामीण परिवहनः असम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) का एक अध्ययन'', एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेस एण्ड ह्यूमैनिटीज, 4(8), 223–234, 2014।*
8. *ओपी, मिनोचा, ''विकास के लिए क्षमता निर्माणः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आकलन'', इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 52(3), 358–369, 2006।*
9. *मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्रधिकरण परियोजना क्रियान्वयन कार्यालय इकाई–1 सागर (म.प्र.)।*
10. *www.ommass.nic-in*